Dr. Savitri

International Research Journal of Management Sociology & Humanities

ISSN 2348 – 9359 (Print)

A REFEREED JOURNAL OF

Explore Innovate Educate

Shri Param Hans Education & Research Foundation Trust

www.IRJMSH.com
www.SPHERT.org

Published by iSaRa

IRJMSH ISSN 2277 – 9809 (0nline) 2348–9359 (Print) Vol 5 issue 9 September 2014

जयपुर जिले में खनिज व उद्योगों का विकसित प्रतिरूप एवं भविष्य की संभावनाए

Dr Savitri
सहायक आचार्य भूगोल,
जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनूं
savi1506@rediffmail.com

HEMRAJ BAIRWA
सीनियर रिसर्चर फैलो, भूगोल विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
Email:raj.hembairwa@gmail.com

Research Paper-शोधपत्र

प्रस्तावना (Introduction)-

"खनिज प्रकृति में पाये जाने वाले ठोस, जड़ तथा रासायनिक पदार्थ है, जो भूगर्भ से खनन क्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते है।" आर्थिक दृष्टि से गुणवत्ता तथा पर्याप्त मात्रा में खनिज उपलब्धता प्रत्येक देश के आधारभूत उद्योगों के विकास के लिए आधार प्रस्तुत करते है। आधारभूत उद्योग (लौह इस्पात, सीमेन्ट, तांबा और एल्यूमिनियम, ही द्वितीयक उद्योगों (मशीन, औजार परिवहन और उपकरण) के विकास को निर्धारित करते है। द्वितीयक उद्योग विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता सामग्रीयों से सम्बन्धित उद्योगों के विकास में सहायक होते हैं।

राजस्थान में खनिज–निर्माण संचयन तथा विभिन्न भौमकीय (Geologicrl) निक्षेप में घनिष्ट सम्बन्ध है। राजस्थान में अरावली के सहारे विस्तृत खनिज पेटी है जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से सम्बन्धित है। धारवाड़ क्रम के अरावली क्रम में तांबा, सीसा तथा जस्ता शिराओं (Veins) में पाया जाता है। राज्य खनिजों की दृष्टि से समृद्व है तथा यहाँ धात्विक, अधात्विक और विभिन्न किस्मों की खनिजों की विविधता के कारण इस खनिजों का अजायबघर तथा रत्नगर्भा वसुन्धरा भी कहा गया है।

राजस्थान में खनिज (Mineral in Rajasthan)

भूगार्भिक निक्षेपों (Deposits) के आधार पर अरावली पर्वतमाला तथा दक्षिणी–पूर्वी पठारी भाग खनिजों के भण्डार व उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। जबकि पश्चिमी राजस्थान में विगत कुछ वर्षो से प्राकृतिक गैस, तेल, लिग्नाईट, चूना पत्थर, ग्रेनाइट और अभ्रक के विशाल भण्डारों का पता चला हे। वर्तमान में राज्य में 67 प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है जिससे से 44 प्रधान तथा 23 गौण खनिज है।

खनिज भण्डार की दृष्टि से राजस्थान झारखण्ड के बाद द्वितीय स्थान पर है और खनन उत्पादन में राजस्थान का पॉचवां स्थान है। राज्य का खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का स्थान बिहार, मध्यप्रदेश, गुजरात तथा असम के बाद पॉचवॉ स्थान है। वोलुस्टोनाइट तथा जारकर का 100% उत्पादन राजस्थान करता है तथा जस्ता, फ्लोराइड, जिप्सम, मार्बल आदि का 90% उत्पादन करता है। राज्य ने वर्ष 2009–10 में फास्फेट, लाईमस्टोन, जिप्सम लिग्नाइट तथा वायु ऊर्जा के क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से कि अधिक उत्पादन तथा प्रभावी कार्य किया है।

जयपुर जिले में खनिज (Minerals in Jaipur District)

जयपुर के पूर्व व उत्तर का क्षेत्र पर्वत श्रेणियों व बहुसंख्या शिखरों से भरा हुआ है। ये पहाड़ियों व शिखर अरावली पर्वत समूह के है। जिले की जलवायु शुष्क व स्वास्थ्यप्रद है तथा विभिन्न

2	चूने का पत्थर सी. जी.	11,899	12,662	23225	20072.3	जयपुर–कोटपूतली, नरायना, फुलेरा
3	रॉकफास्फेट	901	916	1704.8	1101.6	जयपुर–अचरोल
4	प्रेल्सपार	71	103	201.14	140.9	जयपुर–डूँगरवाडा, मंदोती, अमरपुर, सकुन
5	सिलिका मिट्टी	235	209	976.93	206.9	जयपुर–झर, सांगोट, चित्तौड़ी, कुण्डाल, धूलायोपुर, मनौता, बांसखो, बरयाल
6	घीया पत्थर	469	525	615.52	520.9	जयपुर
7	एस. बेस्टास	21	24	13.46	17.8	जयपुर
8	केल्साइट	–	–	124.24	82.97	जयपुर, बरना की चोकी, तारकोला, साखून
9	अभ्रक	–	–	–		जयपुर–बंजारी, लक्ष्मी, भोजपुरा, माधोराजपुरा, कर्नवा का बास
10	नमक		13.76			सांभर
11	अभ्रक	–	–	–	–	बंजारी, लक्ष्मी
स गौणा खनिज						
1	चीनी मिट्टी	–	–	–	–	फतेहपुरा, किरारोपुरा, गोल, जोनपुरा
2	संगमरमर (ब्लॉक)	2040	2753	675658	4059.0	जयपुर, आमेर, ऑधी, रायसला, निमला, भैसलाना
3	ग्रेनाइट (ब्लॉक)	–	–	210.88	52.7	जयपुर
4	ताँबा	–	–	–	–	लाडेरा, सांखू, क्षेत्र
द आणविक खनिज						
1	बेलिलियम	–	–	–	–	बंदरसींदरी, गुजरवाड़ा

स्थानों पर सर्दी व गर्मी अत्यधिक होती है। जिले की अधिकांश नदियों व पहाड़ियों का अद्भूत नजारा मिलता है। सॉभर जिले का ही नहीं वरन् देश का प्रमुख उद्योग है। जयपुर समुद्र तल से 122–183 मीटर ऊँचा है, तथा भूगर्भीप जल का स्तर लगभग 70 मीटर है।

यहाँ पर विविध प्रकार के खनिज मिलते है, जिनमें मृतिका, ताँबा, डोलोमाइट, लोहा, चूना, पत्थर, काँच, रेत और सेलखड़ी प्रमुख हे। जयपुर जिला लाख व हाथीदांत का काम, सांगानेरी एवं बगरू छपाई, पीतल की नक्काशी, ब्लूपोटरीज, रत्न व्यवसाय और संगमरमर की मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्व हैं।

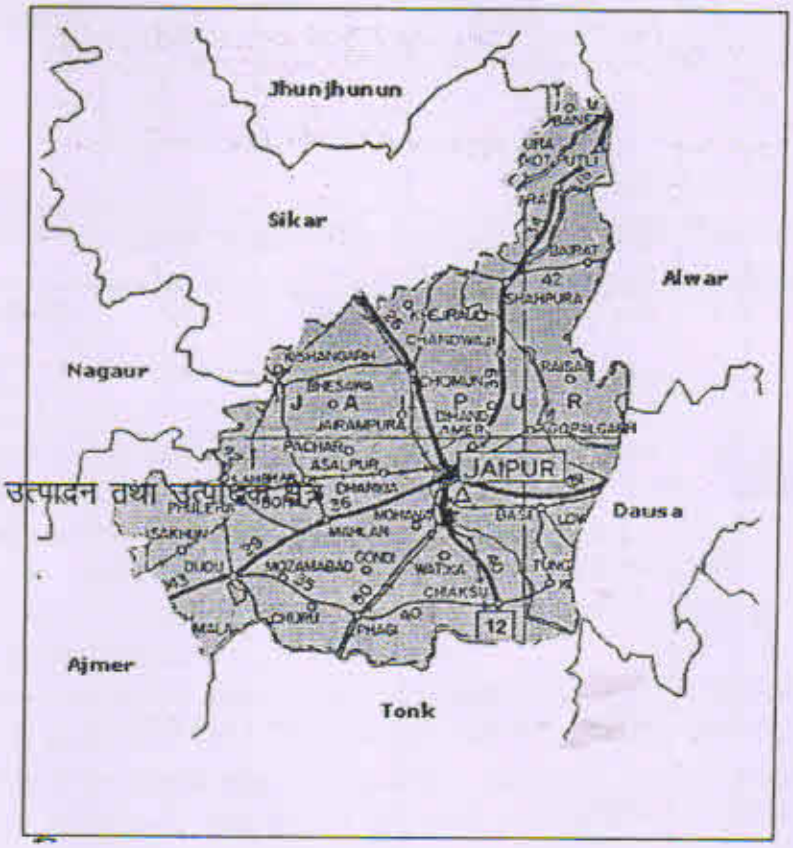

सारणी जयपुरः प्रमुख खनिजों का उत्पादन तथा उत्पादन क्षेत्र

		उत्पादन (हजार टनों में)				उत्पादन क्षेत्र
		1995–96	1996–97	03–04	06–07	
अ. धात्विक खनिज						
1	लोहा अयस्क (हेमेटाइट)	59	35	14.56	43.572	जयपुर–मोरीजा बनोल, तातेरी टोडा, चिपलाटा, थोई, बनिया का बागावास और भाटों की गली
ब. अघात्विक खनिज						
1.	डोलोमाइट	17	33	195.6	316.4	जयपुर–उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र (मध्य में)

1980–81	107.05
1986–	592
1991–92	1600
1993–94	1800
1997–98	2000
2004–05	2102

तालिका में प्रदर्शित विभिन्न वर्षो के खनिज उत्पाद मूल्यों से स्पष्ट है कि राजस्थान में खनिज उत्पादन आप में तेजी से वृद्वि हुई है।

2. **रोजगार में भूमिका**:– राजस्थान की कुल कार्यरत जनसंख्या में से लगभग 4.5 लाख लोग खनिज उद्योग एवं खनिज कार्यो में लगे हुए है। 1951 में राज्य में खनिज कार्यो में 32 हजार लोगों का रोजगार था जो बढ़कर 1989–85 में 1.5 लाख हो गया। 2005–06 में लगभग 5.32 लाख व्यक्ति राजस्थान में खनिज कार्यो में रोजगार पा रहे है तथा 20 लाख व्यक्तियों को परोक्ष रोजगार मिला हुआ है।
3. **खनिज आधारित उद्योगों का विकास**:–राजस्थान में खनिजों का विपुल भण्डार हौ यहाँ अनेक खनिज आधारित उद्योग विकसित हुए है। ये उद्योग खनिजों के आधार पर ही विकसित हुए है जैसे:–सीमेंट उद्योग, घीया पत्थर, पाउडर उद्योग, हिन्दुस्तान जिंक स्मेलटर (उदयपुर), सोडियम सल्फेट कारखाना (डीडवाना), अभ्रक ईंट कारखाना (भीलवाड़ा) आदि। इन उद्योगों के विकास से देश व राज्य के उत्पादन, रोजगार तथा निर्यातों में वृद्वि हुई हैं।
4. **राज्य सरकार की आप का स्त्रोत**:–राज्य सरकार को खनिजों से रायल्टी तथा बिक्रीकर के रूप में राजस्व की प्राप्ति होती है। इस राजस्व में तीव्रगति से वृद्वि हुई है। जहाँ 1970–71 में इनसे प्राप्त होने वाला राजस्व केवल 284 लाख रूपये था, वहाँ 1993–94 में वह बढ़कर 100 करोड़ के करीब पहुँच गया। खनन क्षेत्र से राज्य को गैर राजस्व 1993–94 में 161.2 करोड़ रूपये प्राप्त हुआ है, 1998–99 में वह खनिज राजस्व 306 करोड़ तक पहुँच गया और 2004–05 में 645 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त होने की आशा है। जिसके भविष्य में बढ़ने की आशा है।
5. **देश के निर्यात में सहायक**:– राजस्थान के अनेक खनिजों की देश के बाहर माँग है। वहाँ इनका निर्यात किया जाता है। इमारती पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर आदि निर्यातों में प्रमुख है, इससे देश का निर्यात बढ़ता है।
6. **सैनिक दृष्टि से महत्व**:– राजस्थान में अणुशक्ति के काम में आने वाले खनिजों के उत्पादन में वृद्वि हुई है। उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में यूरेनियम की खानें है तो अजमेर राजगढ़ में लिथियम की खाने है। राजस्थान में बौरिल की खाने है। ये खनिज देश में सैनिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
7. **आवासीय सजावट में योगदान**:–राजस्थान में इमारती पत्थरों तथा संगमरमर ने देश में आवास गृहों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा होटलों आदि की सजावट में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
8. **मौसमी रोजगार**:–प्रदेश में खनिज उद्योगों नें ग्रामीण श्रमिकों को अकाल व खाली समय में बेरोजगार लोगों को रोजगार देने में सहायता प्रदान की।

उपर्युक्त विवचेन से स्पष्ट है कि राजस्थान के आर्थिक विकास में खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका हैं।

राजस्थान की खनिज की नवीनतम विशेषताएँ:–

1. राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी–पूर्वी भाग में खनिजों का जमाव अधिक है। कुछ पश्चिमी राजस्थान में भी पाये जाते है। पूर्वी एवं उत्तरी भाग अपेक्षा कृत खनिज रहित है।

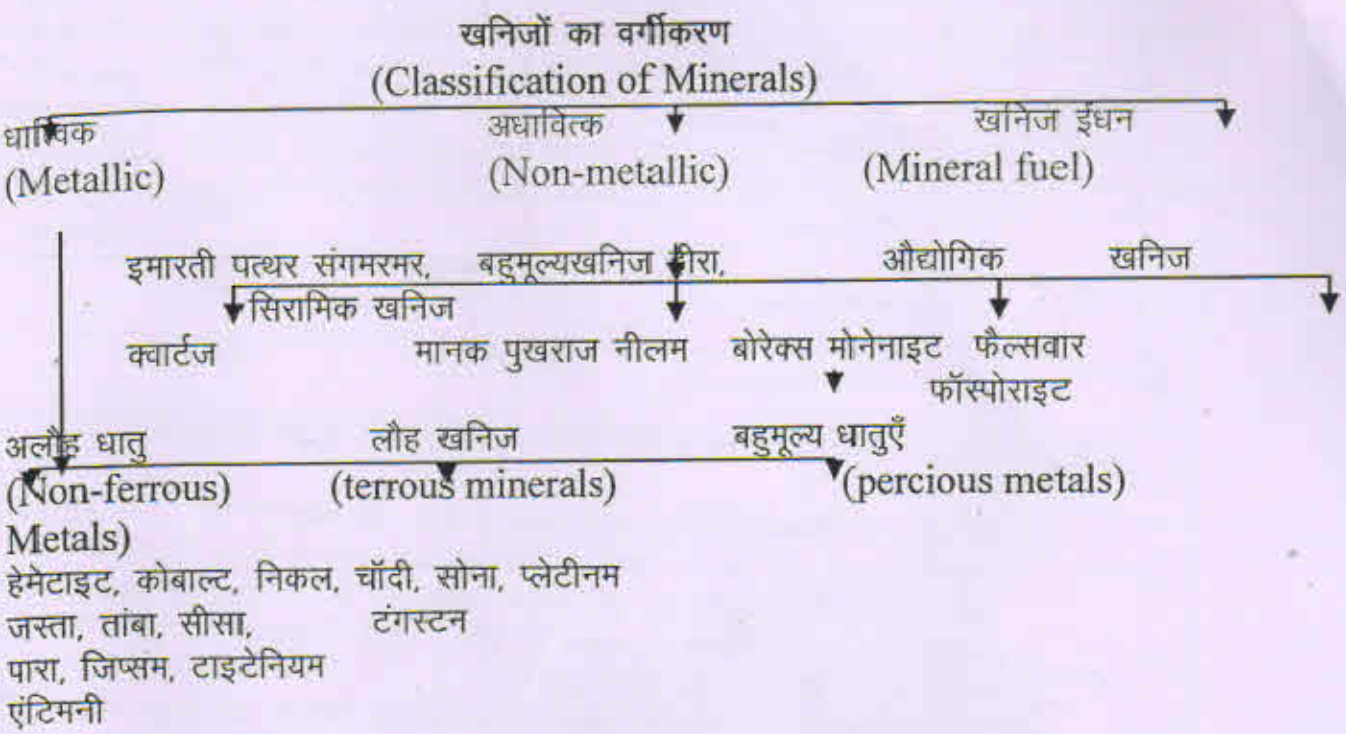

राजस्थान/जयपुर के आर्थिक विकास में खनिजों का योगदानः–

खनिज आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार है। ये अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के लिए विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। कृषि, परिवहन संचार, उद्योग, शक्ति के साधन, आधुनिक युद्व व अन्तरिक्ष विज्ञान सभी क्षेत्रों के विकास में खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉ. हेरोन ने राजस्थान के खनिजों की स्थिति के सम्बन्ध में लिख है कि "सर्वेक्षणों से यह सिद्व हो गया है कि राजस्थान निश्चित रूप से देश के मुख्य खनिज उत्पादकों में से एक है और खनिज संसाधनों के अधिकतम औद्योगिक सम्भावनाओं से परिपूर्ण व घनी है।" खनिजों की दृष्टि से राजस्थान को खनिजों का अजायबघर की संज्ञा दी है। यहॉ वर्तमान में 44 किस्म में बड़े खनिज तथा 23 लघु खनिज उत्पादित होते है। इन खनिजों से राज्य को न केवल आप की प्राप्ति होती है, बल्कि रोजगार भी मिलता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था मे इन खनिजो का महत्वपूर्ण भूमिका है।

राजस्थान के आर्थिक विकास में खनिज की भूमिका (महत्व) का विवेचन निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत किया गया है:–

1. **राजस्थान घरेलू उत्पत्ति में खनिजों की भूमिकाः**–राजस्थान के विशुद्व घरेलू उत्पादन में खनिजों से प्रतिवर्ष 1600–1800 करोड़ रूपये का उत्पादन प्राप्त होता है जो राज्य के कुल विशुद्व उत्पादन का लगभग 9% भाग है। राजस्थान में निरन्तर खनिजों के उत्पादन में वृद्वि हो रही है और इसके अनन्तर ही उसके उत्पादन मूल्य में भी वृद्वि हो रही है जिसे अग्रलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है:–

राजस्थानः खनिजों से प्राप्त आप (1950–51 से 2004–05)

वर्ष	खनिजों का विक्रय मूल्य (करोड़ रू.में)
1950–51	3.5
1960–61	6.5
1970–71	14.0

वर्षों में, उच्च कोटि के लौहा अयस्क 32 वर्षों में, मैंगनीज 31 वर्षों में, स्वर्ण 10 वर्षों में तथा जस्ता 50 वर्षों में समाप्त हो जाऐंगें। पेट्रोलियम संसाधन की तो पहले से ही कमी है। अतएव भारत को एक विवेकपूर्ण संरक्षण नीति की आवश्यकता है जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर बल देना आवश्यक है–

1. जिन खनिजों की आपूर्ति कम है, उनकी प्रति स्थानी विकसित करने के लिए नये शोध किये जायें।
2. खनिजों का अपव्यय रोकने तथा उपजात पदार्थों को समुन्नत करने के लिए नयी प्राविधिकी प्रयुक्त की जायें।
3. अपव्यय परक खनन पर नियंत्रण हो।
4. खनन क्षेत्रों तथा प्रसंस्करण संयंत्रों (Processing Plants) में उचित अवसंरचना का विकास किया जायें।
5. परिवहन व्यय घटाने के लिए प्रसंस्करण संयंत्र खनन क्षेत्रों के निकट स्थापित किये जायें।
6. खनिजों के नये क्षेत्रों की खोज की जायें।
7. संघृत (बहनीय) खनन (Sustainable mining) पर बल दिया जायें।

राष्ट्रीय खनिज नीति (National Minerals Policy)

देश में 1948 में एक नई खनिज नीति अपनाई, जो 1948 तथा 1956 की औद्योगिक नीति का अंग थी। इसमें बही पूंजी निवेश तथा उन्नत प्राविधिकी का प्रयोग करने वाले उद्योगों के लिए आवश्यक कुछ खनिज कच्चे मालों को केन्द्र सरकार के नियंत्रण में रखा गया है। तदनुसार कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लौह–अयस्क, मैगनीज, स्वर्ण, हीरा, तॉबा, सीसा, जस्ता, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, निकिल, प्लेटिनम, गन्धक तथा आणविक ईधनों का दायित्व केन्द्र सरकार को सौंपा गया, जबकि गौण खनिजों को राज्य सरकारों के नियंत्रण में रख गया। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में विदेशी सहयोग को खनिज संसाधन विकास के कुछ क्षेत्रों तक सीमित रखा गया।

खनिजों के विकास के लिए अनेक संगठन स्थापित किये गये जिनमें–भारतीय कोयला लिमिटेड (CIL), तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ONGC), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC), हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL), हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL), भारत गोल्ड माइन्स (BGM), यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया, भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (BALCO), नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (NALCO), मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन, नेशनल कोल डॅवलपमेन्ट कार्पोरेशन, मिनरल्स एण्ड मेट्ल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (MMTC),इण्डियन ब्यूरो ऑफ माइन्स (IBM) आदि सम्मिलित है।

नयी खनिज नीति 1993 में लागू की गई जिसके प्रमुख उद्देश्य एवं दिशा निर्देश निम्नवत् है

1. इलेक्ट्रानिकल हाईटेक उद्योगों के लिए आवश्यक खनिज, सामरिक महत्व के खनिज तथा विरल आपूर्ति वाले खनिजों के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए स्थल तथा अपटतीय क्षेत्रों में खनिज सम्पदा की खोज तथा पहचान की जायें।
2. खनिज संसाधनों का विकास इस प्रकार हो जिससे देश की वर्तमान एवं भावी दीर्घ अवधि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते खनिज कच्चे मालों की नियमित आपूर्ति, खनिजों के प्रसंस्करण तथा संरक्षण के लिए कुशल उपाय तथा खोज की वैज्ञानिक विधियों सुनिश्चित हों।

   नई खनिज नीति में उच्च मूल्य वाले खनिजों की खोज तथा खनन कार्य में विदेशी निवेश तथा प्राविधिक सहभागिता को भी आमंत्रित किया गया है तथा संयुक्त प्रयासों को प्रोत्साहन दिया गया है।
3. उचित उपायों द्वारा खनन द्वारा वनों, पर्यावरण तथा पारिस्थितिक की पर होने प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जायें। नई खनिज नीति के तहत पारिस्थितिक रूप से मंगुर तथा जैव–विविधता से समृद्व क्षेत्रों में सामान्यतः खनन क्रिया नही की जा सकेगी।
4. खनिजों के विदेशी व्यापार को समुन्नत किया जायेगा। खनिजों का निर्यात मूल्य अभिवृद्वि के रूप में करने के प्रयास किये जायेंगे।
5. खनिजों के शोध एवं विकास, प्राविधिकी सुधार खनन विधियों एवं प्रसंस्करण को समुन्नत किया जायेगा।

2. राजस्थान के 95% से अधिक धात्विक खनिजों–लोहा अभ्रक, सीसा, जस्ता, ताँबा केडमियम, बेरिलियम, बोल्फमाइट, चांदी, मैगनीज आदि का उत्पादन राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी–पूर्वी भाग एवं अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से होता है। जयपुर में एस्वेटॉस, फैल्सपार, मुल्तानी मिट्टी, खड़िया पत्थर, नमक व टंगस्टन आदि खनिजों का उत्पादन होता है।
3. राज्य को कुछ खनिजों में एकाधिकार प्राप्त है जैसे वह भारत के कुल जिप्सम उत्पादन का 92% , धीया पत्थर 90%, चाँदी 90%, चूने का 93%, उत्पादित करता है। जबकि राजस्थान जेस्पार, तोमड़ा (Gamet), बुलेस्टोनाइट तथा पन्ना (Emrald) देश का एक मात्र उत्पादक राज्य है।
4. राज्य के कई महत्वपूर्ण खनिजों में यथा–ताँबा, इमारती पत्थरों, टंगस्टन, एस्बेस्टॉस, जस्ता तथा सीसे का उत्पादन होता है।
5. प्रदेश में ईंधन, ऊर्जा एवं लौह धात्विक खनिजों का उत्पादन नगण्य है। बेन्टेनाइट, ग्रेफाइट, लोहा, कोयला, मैंगनीज, कियोनाइट भी बहुत कम मात्रा में मिलता है।
6. राजस्थान अधात्विक खनिजों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है जिनमें से अधिकांश का विदोहन पश्चिमी राजस्थान में होता है।
7. राजस्थान के खनिजों का विस्तृत एवं गहनता से सर्वेक्षण अभी तक नहीं हो पाया है।
8. अजमेर की भिनाय तहसील के छछंदरा व जोशवरपुरा तथा दोसा जिले में कुछ मात्रा में सोना, तांबा, चांदी, सीसा, जस्ता व अभ्रक प्राप्त होने की संभावना है।

खनन उद्योग की समस्याएँ (Problems of Mining Industry)

भारत/राजस्थान/जयपुर की खनिज सम्पदा समृद्व होने के बावजूद राज्य में उद्योग की दशा शोचनीय है। वह निम्नलिखित समस्याओं से ग्रस्त है:–

1) राजस्थान में खनिज संसाधनों के निष्कर्षण तथा संसाधित करने की उचित नीति का अभाव है। पट्टेदार खनन में अवैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करते है जिससे अधिक अपव्यय एवं पर्यावरण को हानि होती हैं
2) खनिजों के खनन एवं समाधान में प्रपुक्त तकनीकी पुरानी तथा घिसी–पिटी है। कुछ खाने अनायिक होने के कारण त्याग दी गयी है।
3) राजस्थान में खनिजों का स्थानिक वितरण विषय है, जिससे उनके वितरण में, विशेषतः रेलो द्वारा, भारी परिवहन लागत आती है।
4) देश में औपनिवेशिक काल से ही खनन उद्योग निर्यातपरक रहा है। खनिजों को अशुद्व रूप ही निर्यात कर दिया जाता है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उनका कम मूल्य प्राप्त होता है।
5) खनिजों संसाधनों की उचित खोज तथा विस्तृत वस्तु–सूची (Inventory) अभी तक तैयार नहीं की गई हैं।
6) राजस्थान खनन उद्योग पूंजी, अवसंरचना, विपणन (Marketing), विदेशी स्पर्द्वा तथा सरकारी संरक्षण सम्बन्धी अनेक समस्याओं से ग्रस्त है।
7) खनिजों के संरक्षण तथा अपव्यय (Wastages) पर नियंत्रण पर बहुत ही कम जोर दिया जाता है। शोध एवं प्राविधिकी के अभाव में निम्न कोटि के खनिजों का दोहन नहीं किया गया जाता है तथा अनेक उपजात पदार्थ (by-products) अनुपपुक्त रह जाते है।
8) अवैज्ञानिक खनन से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर्यावरणीय कानून को सख्ती से लागू करने पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बेइमान खनिक, खनिजों के समाप्त होने पर उस क्षेत्र को उचित उपचार के बिना ही त्याग देते है परिणायतः ऐसे क्षेत्र बंजर भूमि में बदल जाते है।

खनिजों का संरक्षण (Conservation of Minerals)-

खनिज अनवीकरण योग्य संसाधन हैं। एक बार समाप्त होने पर, उनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, वे भावी पीढ़ियों के लिये धरोहर है। अतएवं यह हमारा नैतिक कर्त्तव्य है कि उनका संरक्षण तथा परिक्षण किया जाये तथा समुचित रणनीति अपनाकर उनके दुरूपयोग एंव अपव्यय को रोका जाये। कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी के कारण उनका सरंक्षण अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार कोकिंग कोपला 13 वर्षो में, गैर–कोकिंग कोयला 116 वर्षो में ताँबा 36

6. नई खनिज नीति, 1993 में प्रमुख खनिजों को खोज एवं दोहन पर सरकार के पूर्ण नियंत्रण की अपेक्षा घरेलू एवं विदेशी निवेशकों को खनन एवं प्रसंस्करण कार्यकलापों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

खनिज आधारित उद्योगो का विकास (Development Minerals Based Industries)

राज्य के खनिजों का समुचित विदोहन करने के लिए खनिज आधारित उद्योगों का विकास किया गया है, जिसमें खेतड़ी में तांबा गलाने का कारखाना तथा उदयपुर में देवारी स्थान पर जस्ता गलाने का कारखाना हिन्दुस्तान जिंक स्मेल्टर स्थापित किया गया है। डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना, भीलवाड़ा, दौसा व उदयपुर में घीया पत्थर का पाउडर बनाने का करखाना।

इमारती पत्थर घिसने, चिप्स आदि की भी अनेक इकाइयाँ राज्य में स्थापित की जा रही है। राजस्थान में सिलिका के उपयोग से काँच उद्योग, क्वार्ट्ज, व चिकनी मिट्टी के बर्तनों के कारखाने स्थापित करने की काफी संभावनाएं है। जैसलमेर में खनिज तेल के भण्डार की प्रबल संभावनाएं है। कोटा में जिप्सम आधारित सल्फ्यूरिड एसिड के निर्माण का संयंत्र लगाने पर सक्रिय रूप से विचार किया जाना चाहिए। उदयपुर में एक पिग लोहा संयंत्र लगाने की आवश्यकता है क्योंकि वहां निकटवर्ती क्षेत्रों के कच्चे लोहे का उपयोग किया जा सकता है।

अब पालना में 2.3 करोड़ टन लिग्नाइट कोयला भण्डारों की सेंभावनास का पता लगा है। राजस्थान में खनिजों के विकास तथा खनिज आधारित उद्योगों का भविष्य काफी उज्जवल हैं भीलवाड़ा के आंगूचा गांव में जस्ते–सीसे के अपार भण्डार मिलने से गुलाबपुरा में एक जस्ता शोधक करखाना स्थापित किये जाने की संभावनाएं बढ़ गई है। कोटा–चित्तौड़गढ़ रेलमार्ग का निर्माण होने से इस क्षेत्र में सीमेन्ट उद्योग स्थापित होने के बहतरीन अवसर है। चित्तौड़गढ जिले के चन्देरिया गांव में सीसे–जस्ते का बड़ा स्मेल्टर संयंत्र लगाया गया है।

उद्योग : श्रमिकों की संख्या (2012–13) में

क्र.सं.	मद	संदर्भ अवधि	संख्या
01	कारखाना अधिनियम के तहत कार्यरत पंजीकृत कारखाने	2013	2410
02	पंजीकृत कारखानों में औसत श्रमिकों सी संख्या	2013	89409
03	उद्योग विभाग द्वारा पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयां	2012–13	2221
04	लघु औद्योगिक इकाइयों मैं औसत अनुमानित दैनिक मजदूर	2012–13	18742
05	औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या	2012–13	42
06	औद्योगिक क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट (करोड़ रू. में)	2012–13	41320.13

राज्य अर्थव्यवस्था में खजिजों का योगदान : एक नजर में

- 2005–06 से 2008–09 में औद्योगिक विकास दर 7.20 रही, जो 2009–10 से लेकर 13–14 तक 6.79 ही रह गई।
- उद्योगों का जीएसडीपी में योगदान 2004–05 में 30.56 प्रतिशत था जो 2013–14 में 28.54 प्रतिशत रह गया।
- कर्ज लेकर घी पीने की नीति के कारण राज्य को 1 लाख 30 हजार 640 करोड़ रूपये का कर्जभार उठाना पड़ रहा है, कुल 2.50 लाख करोड़ का कर्ज है।

- 2007–08 में 1650 करोड़ रूपए का रेवेन्यू सरप्लस था, जो 2013–14 में 2500 करोड़ के राजस्व घाटे में तब्दील हो गया।

(नोटः ये सभी ऑकड़े पिछली सरकार (कांग्रेस) के कार्यकाल के है।)

निष्कर्ष (Conclution)-

जून 1998 में घोषित नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य जिले के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में विनियोग की दृष्टि से सबसे ऊँची प्राथमिकता वाला जिला बन सकें। तभी यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अपना स्थान बना सकेगा।

नई नीति में विकास पर विशेष बल दिया गया और इसमें समूहों का विकास (Development of Clusters) की रणनीति अपनाई गई ताकि समूहों की किफायतों (Economics of agglomeration) व प्रमुख क्षेत्रों की प्रगति को सुनिश्चित किया जा सकें। इसमें आधारभूत ढांचे के सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है तथा विकास व रोजगार की दृष्टि प्रमुख क्षेत्रों के विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है।

राज्य की नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 2008 की अवधि में 20 हजार करोड़ रूपये का विनियोग किया गया ताकि औद्योगिक उत्पादन की दर को 12 प्रतिशत किया जा सकें।

उद्देश्यः (1) राजस्थान में औद्योगिक विकास की नीति को तेज करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। (2) 1994 की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत जो कमियाँ अनुभव की गई, उन्हें नई औद्योगिक नीति में दूर करने का प्रयास किया गया है।

संदर्भ (Referencess) :–

1. मामोरिया चतुर्भुज एवं सिसौदिया एम.एस. पर्यावरण एवं विकास साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आगरा (M.P.) 2007
2. द्विवेद्वी ए.पी.एच. चतुर्वेदी जे.के. भू प्रबंधन एवं संरक्षण हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़, 1997
3. राव वी.पी. एवं श्रीवास्तव वी.के. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर (यू.पी.) 2006
4. भल्ला एल. आर. राजस्थान का भूगोल, 2012 पंचशील प्रकाशन, जयपुर (राज.)
5. संसाधन और पर्यावरण, डॉ. वी.पी. राव, वसुन्धरा प्रकाशन, 236 दाडदपुर, गोरखपुर (यू.पी.)
6. राजस्थान एक समग्र अध्ययन, 2009 डॉ. प्रवीण झा, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, झालना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर (राज.)
7. कुमार प्रमीला एवं शर्मा श्रीकमल, औद्योगिक भूगोल, 2009 मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, रवीन्द्र नाथ ठाकुर मार्ग, बानगंगा, भोपाल (एम.पी.)
8. शुक्ला, लक्ष्मी 1987 'एनवायरनमेन्टल एप्रेजल ऑफ राजस्थान' एण्ड अपब्लिश्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, पृ.सं. 311
9. क्लार्क पी. 1966 इण्डस्ट्रीयल लोकेशनल एण्ड इकोनोमिक पोटेन्शियल लाइडस बैंक रिव्यू पृ. सं. 82–87.
10. चौधरी, एम.आर. 1970 इण्डियन इण्डस्ट्रीज, डवलपमेंट एण्ड लोकेशनल, इण्डिया बुक हाऊस, कोलकाता (भारत)
11. एन्वायरनमेंन्ट असेसमेन्ट रिपोर्ट, जयपुर, राजस्थान दिसम्बर 2012.
12. इण्डस्ट्रीज पोटेशियम सर्वे जयपुर डिस्ट्रिक, मई 2013
13. गजेटियर ऑफ राजस्थान, 2012
14. प्रतियोगिता दर्पण, मई 2012
15. द हिन्दू डेली न्यूज पेपर, 2013 पृ. सं. 12–13
16. योजना और कुरूक्षेत्र क्रमशः दिसम्बर माह (2013) और नवम्बर (2012) मन्थली पत्रिका।